

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2074/2011

मैसर्स गोमती मिनरल्स एंड मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन कंपनीज एक्ट, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1289, फौजदार हाउस, बाबा हरीश चंद्र मार्ग, चांद पोल बाजार, जयपुर में है, अपने निदेशक श्री आनंद कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार शर्मा, जिनकी आयु लगभग 54 वर्ष है, निवासी 1289, फौजदार हाउस, बाबा हरीश चंद्र मार्ग, चांद पोल बाजार, जयपुर के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव, खान विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- उप सचिव, खान विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर क्षेत्र, खनिज भवन, जयपुर।
- अधीक्षण खनन अभियंता, जयपुर क्षेत्र, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, जयपुर।

----प्रतिवादी

से संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1978/2011

भूषण शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद कुमार शर्मा, जिनकी आयु लगभग 40 वर्ष है, निवासी 1289, फौजदार हाउस, बाबा हरीश चंद्र मार्ग, चांद पोल बाजार, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सरकार के सचिव, खान विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

- 2. उप सचिव, खान विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर।
- 3. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर क्षेत्र, खनिज भवन, जयपुर।
- 4. अधीक्षण खनन अभियंता, जयपुर क्षेत्र, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5. खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री के.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री योगेश कल्ला के साथ
प्रतिवादी के लिए	:	श्री राहुल लोढ़ा, ए.जी.सी.

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

आदेश

29/11/2024

- 1. इन दोनों याचिकाओं का निर्णय इस आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा समान है। सुविधा के लिए, तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2074/2011 से लिए जा रहे हैं।
- 2. यह याचिका दिनांक 06.10.2003, 12.03.2010 और 09.11.2010 के उन आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिनके द्वारा क्रमशः पट्टा विलेख को रद्द किया गया था और अपीलों को खारिज किया गया था।
- 3. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दिनांक 28.05.1987 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को खनन पट्टा प्रदान किया गया था और ग्राम संकोतरा, तहसील जमवा रामगढ़, जिला जयपुर में स्थित 9000 वर्ग मीटर का क्षेत्र आवंटित किया गया था। प्रारंभ में, पट्टा दस वर्षों के लिए था और उसके बाद, बीस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया।

याचिकाकर्ता कंपनी को दो खनन पट्टे आवंटित किए गए थे और तीसरा खनन पट्टा कंपनी के निदेशक के नाम पर था। ये तीनों खनन क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए थे।

राजस्थान राज्य खनिज नीति 1994 (संक्षेप में '1994 की नीति') के अनुसार, वन क्षेत्र से सटे खनन क्षेत्र के लिए, सुरक्षा गलियारा बनाए रखा जाना था। याचिकाकर्ता ने सुरक्षा गलियारे के लिए क्षेत्र समर्पित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप खनन के लिए 7750 वर्ग मीटर क्षेत्र शेष रहा। समर्पित क्षेत्र को दर्शाने के बाद एक संशोधित योजना प्रस्तुत की गई। खनन योजना को दिनांक 21.08.2003 के संचार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

तीनों पट्टा क्षेत्रों को एक में संयोजित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। अनुरोध इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि तीन में से दो पट्टा विलेख पहले ही रद्द किए जा चुके थे और अपीलें लंबित थीं।

यद्यपि, राजस्थान खान और खनिज रियायत नियम, 1986 (संक्षेप में '1986 के नियम') के नियम 65 के तहत छूट की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रारंभ में खनन के लिए आवंटित भूमि एक हेक्टेयर से कम थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दायर किया। अधीक्षण खनन अभियंता ने दिनांक 06.10.2003 के आदेश द्वारा खनन पट्टा रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः 04.02.2010 और 09.11.2010 को खारिज कर दी गईं। अतः, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रद्द करने का आदेश बिना नोटिस जारी किए पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि रद्द करने का आधार यह था कि खनन के लिए बचा हुआ क्षेत्र एक हेक्टेयर से कम था, जबकि याचिकाकर्ता को आवंटित मूल क्षेत्र एक हेक्टेयर से कम था। यह तर्क है कि यदि सभी तीनों खनन पट्टों को संयोजित किया गया होता, तो उपलब्ध क्षेत्र 1.96 हेक्टेयर होता। निवेदन है कि 1994 की नीति द्वारा लगाई गई शर्त कि एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र खनन पट्टे के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा, भूतलक्षी नहीं थी।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने चुनौतीप्राप्त आदेश का बचाव करते हुए निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा क्षेत्र का समर्पण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और उस पर लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसरण में था।
6. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि रद्द करने का आदेश कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया था और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता को मामले का बचाव करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। विलय के लिए आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दो पट्टा विलेख पहले ही रद्द किए जा चुके थे और अपीलें लंबित थीं। इस तथ्यात्मक पहलू को अनदेखा कर दिया गया कि दो पट्टा विलेखों को रद्द करने का कारण यह था कि प्रत्येक पट्टा विलेख में क्षेत्र एक हेक्टेयर से कम था। यह मुद्दा कि क्या 1994 की नीति पहले से स्वीकृत पट्टा विलेखों पर लागू होगी, अधिनिर्णित नहीं किया गया था।
7. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, चुनौतीप्राप्त आदेशों को निरस्त किया जाता है और मामले को प्रतिवादी संख्या 4 को वापस भेजा गया है ताकि वह याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार इस मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय ले।
8. रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।
9. सभी लंबित आवेदन(ओं) का निपटान किया जाता है।

(अवनीश झिंगन), जे.

सिम्पल कुमावत / 33-34

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

